वित्त विभाग

(विनियम)

144

दिनांक 16 जून, 1997

संख्या 2/2/94-3एफ.आर.II.---भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इस के द्वारा, पंजाब खजाना नियम, जिल्द I को हरियाणा राज्यार्थ आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :---

1. ये नियम पंजाब खजाना जिल्द I (हरियाणा प्रथम संशोधन) नियम, 1997, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब खजाना नियम, जिल्द I (जिन्हें इस में इस के बाद उक्त नियम कहा गया है में, अध्याय IV में, अनुभाग I में, खण्ड क में, उपखण्ड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :---

"(viii) "संव्यवहार की निकटतम रुपये में संगणना।"

3. उक्त नियमों में, नियम 4.10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :---

"4.10 एक रुपये के भागांश वाले सभी सरकारी संव्यवहार रुपये का निकटतम पूर्णांकन करते हुये लेखा में लिये जायेंगे (50 पैसे और अधिक भागांश को अगले रुपये को पूर्णांकित करना है तथा 50 पैसे से कम भागांश को छोड़ दिया जायेगा)।

(1) वेतन तथा भत्ते, पैंशन अथवा यात्रा भत्ते बिल में प्रत्येक अलग-अलग मद का सरकारी कर्मचारियों तथा पैंशन भोगियों को भुगतान तथा से वसूलियां, इस नियम में दी गई रीति में, निकटतम रुपये में पूर्णांकित करते हुये की जायेंगी, परन्तु :---

(क) परिनियम द्वारा नियम परिलब्धियों की दशा में, 50 पैसे से कम रुपये के भागांश वाली राशि भी निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जायेंगी।

(ख) भविष्य निधि तथा कर्मचारी जीवन बीमा प्रीमियम से भिन्न सेवा के मद्दें कटौतियों की दशा में, इस नियम के उपबन्धों के अनुसार किसी वर्ष के प्रथम ग्यारह महीनों के दौरान सरकारी कर्मचारी से की गई कुल वसूलियों तथा निधियों इत्यादि को लागू नियमों के अधीन समग्र रूप से वर्ष के संबंध में वसूली योग्य राशि के बीच अन्तर, यदि कोई हो, अतिरिक्त अथवा अल्प वसूली द्वारा जैसी भी स्थिति हो, की जायेगी, यद्यपि वह निकटतम पूर्ण रुपये में नहीं है।

(ग) यात्रा भत्ता बिलों की दशा में, पूर्णांकन केवल अन्तिम स्तर पर किया जायेगा न कि किसी व्यक्ति के दावे में समाविष्ट प्रत्येक मद्द अर्थात् रेलवे किराया, मील दूरी, तथा दैनिक भत्ता के संबंध में।

(घ) स्थानीय खरीदों के लिये छोटे-मोटे नकद भुगतान, कार्यालय अध्यक्ष के पास उपलब्ध स्थायी नकद अग्रदाय में से किए जाते हैं और अग्रदाय की आपूर्ति के लिये उप वाउचरों द्वारा (जहां आवश्यक हो) सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रतिपूर्ति बिल सम्बद्ध खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी को नियत काल पर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, यथासंभव, सप्लाईकर्ता को प्रत्येक अवसर पर उनको भुगतान योग्य राशी को निकटतम रुपये में पूर्णांकित करने में सहयोग करने के लिये मनाना चाहिये। आपवादित मामलों में, जहां भुगतान पैसे का छोड़ा न जा सकता हो, वहां प्रतिपूर्ति के लिये चाहे गए उप वाउचरों के कुल जोड़ में पैसे भी शामिल होंगे। फिर भी, प्रतिपूर्ति बिल सम्बद्ध खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी को केवल पूर्ण रुपये के भाग के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। तथापि, मुख्य पुस्तक तथा छोटी-मोटी नकद पुस्तक में संव्यवहारों को संतुलित करने के प्रयोजन के लिये, प्रदान तथा वितरण अधिकारी---

(क) स्थायी पेशगी की प्रतिपूर्ति में प्राप्त वास्तविक राशि दर्शाना,

(ख) "संव्यवहारों का पूर्णांकन" की एक मद के रूप में अप्रतिपूरित पैसे को अभिलिखित करेगा,

145

(ग) उस बिल के विवरणों को देते हुये जिसमें यह राशि कम प्राप्त की गई थी पश्चातवर्ती प्रतिपूर्ति बिल के माध्यम से दावा करने के लिये आगे ले जायेगा,

(ङ) रद्दी कागजों अथवा पुराने समाचार पत्रों, नियतकालित पत्रिकाओं, बेकार फर्नीचर इत्यादि, की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों की दशा में, वसूल की जाने वाली राशियों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जानी चाहिये तथा किसी पक्षकार से संव्यवहारों की कुल राशि में, जिसके लिये केवल एकल रसीद दी दी जाती है, पैसे शामिल नहीं होने चाहियें, ताकि सरकारी लेखों में प्राप्तियां केवल पूर्ण रुपयों में ही जमा की जाएं,

(2) एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच अथवा उसी सरकार के दो विभाग के बीच संव्यवहार, जब तक मूल संव्यवहारों से हटाना संभव न हो, एक रुपए का भागांश जो वास्तव में पूर्ण रुपया नहीं है,

(3) स्टर्लिंग अन्य विदेशी मुद्राओं से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित राशि,

(4) आकस्मिक और अन्य प्रभारों के संबंध में दावों के लिये भुगतान, जब दावेदारों को कोई आपत्ति न हो, परन्तु निकतम रुपए में एक रुपये के भागांश का पूर्णांकन, किसी बिल पर, केवल भुगतान योग्य निवल राशि के संबंध में किया जायेगा न कि बिल में दावों या समायोजन की अलग-अलग मदों के संबंध में,

(5) किसी विधि द्वारा या के अधीन अथवा सरकार की किसी संविदात्मक बाध्यता के अधीन नियत देयों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशियों से भिन्न, रिजर्व बैंक के प्रेषण,

(6) किसी विधि द्वारा या के अधीन नियत या इस नियम के प्रवर्तन से सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त से भिन्न, सरकार के पक्ष में निक्षेप तथा वसूल किये गये राजस्व,

(7) दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पूर्व जारी किये गये परन्तु 1 जनवरी, 1996 के बाद भुगताने के लिये प्रस्तुत किये गये आंशिक भुगतान के चेक, मूल चेकों की राशि के स्थान पर गुम/कालवर्जित चैकों के स्थान पर, जारी किए जाने के लिये अपेक्षित नए चैक तथा उसी रूप में भुनाने के लिये बैंक में प्रस्तुत किए जाएं,

(8) पूर्व वर्षों के लेखों में शीर्ष "पी.ए.ओ. उच्चन्त" तथा अन्य निक्षेप ऋण तथा प्रेषण इत्यादि, के अधीन संगणित आंशिक संव्यवहारों का समायोजन/समाशोधन, पूर्णांकित किए बिना वास्तविक आधार पर प्रभावित किया जा सकता है,

(9) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "पूर्ण घोषित" रिपोर्ट किये गये पूर्व वर्षों के संव्यहार ही केवल जवाबी हैं तथा वास्तविक आधार पर लेखों में समायोजित किये जायें,

(10) पूर्व वर्ष के गलत संव्यहारों की परिशुद्धि वास्तविक आधार पर की जाएगी "।

(11) यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू समझी जाए।

ए० एन० माथुर,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

## FINANCE DEPARTMENT

## REGULATION

The 16th June, 1997

**No. 2/2/94-3FR II.**—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Treasury Rules, Volume-I, in its application to the State of Haryana namely :—

1. These rules may be called the Punjab Treasury Volume-I (Haryana 1st Amendment) Rules, 1997.

2. In the Punjab Treasury Rules, Volume-I (hereinafter referred to as the said rules) in Chapter IV, in Section I, in clause A, for sub-clause (viii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(viii) Calculation of transaction to the nearest rupee".

3. In the said rules for rule 4.10, the following sub-rule shall be substituted namely :—

"4. 10. All Government transactions involving fraction of a rupee shall be brought into account by rounding off to the nearest rupee (fraction of 50 paise and above to be rounded off to the next rupee and the fraction of less than 50 paise to be ignored).

1. Payment to and recoveries from Government employees and pensioners, each individual item in pay and allowances, pension or TA bill being rounded off to the nearest rupee, in the manner laid down in this rule ; provided that :—

(a) in the case of emoluments fixed by Statute amount involving fractions of a rupee less than 50 paise shall also be rounded off to the next rupee ;

(b) In the case of deduction on account of service other than Provident Fund and Personnel Life Insurance, Premia, the difference, if any, between the total recoveries made from a Government employee during the first eleven months of a year in accordance with the provisions of this rule and the amount recoverable in respect of year as a whole under the Rules applicable to the Funds etc. shall be adjusted in the last month of the year by additional or short recovery, as the case may be, even if the same is not in the nearest whole rupee ;

(c) in the case of travelling allowance bills the rounding shall be done only at the last stage and not in respect of each item e. g. railway fare, mileage and daily allowance, comprising the claim of an individual ;

(d) petty cash payments for local purchases, are met out of permanent cash imprest available with the head of office and recoupment bill duly supported by sub-vouchers (where necessary) is required to be preferred periodically to the Treasury Officer/Assistant Treasury Officer concerned for replenishment of the imprest. As far as possible supliers should be persuaded to cooperate in rounding off the amount payable to them on each occasion to the nearest rupee. In exceptional cases where payment of paise can not be avoided, the total of the sub-vouchers sought to be recouped would include paise also. Nevertheles, the recoupment bill shall be submitted to the Treasury Officer/Assistant Treasury Officer concerned for the whole rupee portion only. However for the purpose of balancing the transactions in the main book as well as in the petty cash book, the Drawing Disbursing Officer will (a) indicate the actual amount received in recoupment of the permanent advance ; (b) record therein the unrecouped paise as an item of-rounding off of transaction and (c) carry it over to be claimed through the subsequent recoupment bill by giving particulars of the bill in which this amount was short received ;

(e) in the case of receipts arising out of sale of waste papers or old newspapers, periodicals, condemned furniture etc. the amount to be realished should be rounded off to the next rupee and not include paise in the sum total of transactions with any party for which a single receipt is given so that the receipts are credited into Government accounts in whole rupees only ;

2. Transactions between one Government and another or between two Departments of the same Government, unless it is not possible to eliminate from the original transactions, fraction of a rupee is not an exact whole rupee ;

3. Amount converted into Indian Currency from Sterling or other foreign currencies ;

4. Payments for claims in respect of contingment and other charges when claimants have no objection ; provided that the rounding off of the fraction of a rupee to the nearest rupee shall be done only in respect of the net amount payable on a bill and no in respect of the individual items of claims or adjustments in the bill ;

5. Reserve Bank remittances, other than of sums representing dues fixed by or under any law or under any contractual obligation of the Government ;

6. Deposits in favour of Government and revenues recovered, other than those which are fixed by or under any law or are specially exempted by the Government from the operation of this rlue;

7. Cheques of fractional payment issued prior to 1st January, 1996 but presented for encashment after 1st January, 1996, fresh cheques required to be issued in lieu of the lost time barred cheques for the amount of original cheques and the same may be presented to the bank for encashment as such ;

8. adjustment/clearance of fractional transactions accounted for under 'PAO' Suspense and other debt deposit and remittance etc. heads in the accounts of the earlier years may be effected on actual basis without rounding off.

9. the transactions of previous years reported "put through" by the R. B. I. are only responding one and may be adjusted in accounts on actual basis ;

10. rectification of erroneous transactions of the earlier year may be carried out on actual basis".

11. This notification will come into force with effect from 1st January, 1996.

A. N. MATHUR,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Finance Department.

## HEALTH AND MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT

The 3rd July, 1997

**No. 16/21/96-3HB-IV.**—In view of the directions of the Supreme Court of India in its judgement dated 9th August, 1996 in the case of T. N. A. PAI *versus* State of Karnataka in W. P. (C) No. 317 of 1993, the Governor of Haryana is pleased to constitute a Committee consisting of the following for fixation of Fee Structure for Private Medical/Dental Colleges to be applicable for the session starting 1997 :—

1. Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Health and Medical Education Department ... Chairperson
2. Vice-Chancellor, Kurukshetra University, Kurukshetra or his nominee ... Member
3. Vice-Chancellor, Maharishi Dayanand University, Rohtak or his nominee ... Member
4. Director, PT. B. D. Sharma, PGIMS, Rohtak ... Member
5. Principal, D. A. V. Centenary Dental College, Yamunanagar ... Member
6. Director Principal, Maharaja Agrasen Institute of Medical Research and Education Society, Agroha (Hisar) ... Member
7. Director Principal, B. R. S. Dental College and Hospital, Kot-Billa (Panchkula) ... Member
8. Joint Secretary, Health ... Member-Secretary.

2. The Committee will discuss the matter in view of Supreme Court direction and after consideration will submit its report to the Government, suggesting a suitable fee structure immediately.

3. The Headquarter of the Committee is Chandigarh where it will hold its meetings.

VEENA EAGLETON,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Health and Medical Education Department.